पाठ - 31

चौधरी चरण सिंह

^‘ मेरे संस्कार उस गरीब किसान परिवार के संस्कार हैं जो धूल और कीचड़ के बीच एक छप्परनुमा झोपड़ी में रहता है, मैंने अपना बचपन उन किसानों के बीच बिताया है जो खेतों में नंगे बदन अपना पसीना बहाते हैं’

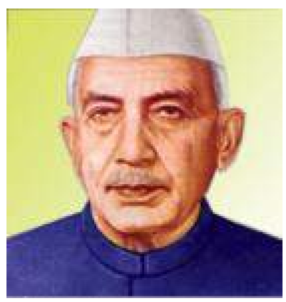

ये शब्द हैं चौधरी चरण सिंह के, जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ परन्तु जो भारत के प्रधानमंत्री के शिखर पद तक पहुँचे। इनका जन्म 23 दिसम्बर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित नूरपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता चौधरी मीर सिंह एक साधारण किसान थे। इनकी माँ का नाम नेत्र कौर था।

प्रारम्भिक शिक्षा जानी खुर्द गाँव में प्राप्त करने के बाद बालक चरण सिंह ने मेरठ के गवर्नमेन्ट हाईस्कूल में शिक्षा ग्रहण की। आगरा कालेज से इन्होंने विज्ञान विषय में स्नातक तथा इतिहास विषय में स्नातकोत्तर (एम0ए0) की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात् उन्होंने मेरठ कालेज से कानून की उपाधि (एल0एल0बी) प्रथम श्रेणी में प्राप्त कर गाजियाबाद दीवानी अदालत में वकालत प्रारम्भ की।

आज़ादी के महासमर में-

अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतन्त्रता की लड़ाई में चौधरी चरण सिंह ने बढ़-चढ़ कर योगदान किया। 1930 में जब महात्मा गांधी ने डाँडी मार्च कर “नमक कानून तोड़ो आंदोलन” चलाया तब गाजियाबाद में यह बीड़ा उठाया नौजवान चरण सिंह ने। गाजियाबाद के लोनी

नामक गाँव में उन्होंने नमक बनाया। उन्हें नमक कानून तोड़ने के जुर्म में छः महीने की सजा सुनायी गयी। आजादी की लड़ाई में उनकी यह पहली जेल यात्रा थी।

9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तथा गांधी जी ने देशवासियों से ''करो या मरो'' का आह्वान किया। ऐसे समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ संभाग में बगावत की बागडोर युवक चरण सिंह ने सँभाली। भूमिगत रहकर उन्होंने गाजियाबाद, हापुड़, मवाना, सरधना, बुलन्दशहर तथा आस-पास के गाँवों में क्रान्तिकारियों का गुप्त संगठन बनाया। इस संगठन ने अंग्रेजी प्रशासन को ठप्प करने की मुहिम चलायी।

कृषि और कृषकों के हित में किये गये कार्य-

15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। केन्द्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इस मंत्रिमंडल में स्वायत्त शासन और स्वास्थ्य विभाग में सभा सचिव का दायित्व चौधरी चरण सिंह को मिला। उनकी छवि एक कुशल, कर्मठ और ईमानदार प्रशासक के रूप में थी। उन्हें जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार करने का काम सौंपा गया। यह विधेयक एक जुलाई 1952 से लागू हुआ। इसकी प्रशंसा विदेशी विद्वानों ने भी की । इस विधेयक का सर्वाधिक लाभ दलितों और पिछड़े वर्गों को हुआ।

पटवारियों के शोषण से किसानों को मुक्ति दिलाकर चौधरी चरण सिंह ने लेखपालों की नियुक्ति की। 1954 में लागू चकबन्दी अधिनियम भी चौधरी चरण सिंह का एक क्रान्तिकारी कदम था। चकबन्दी से किसानों को यह लाभ हुआ कि उनकी फसलों की सुरक्षा तथा सिंचाई के लिये पानी का प्रबन्ध सुविधाजनक हो गया। इससे मानवश्रम की बचत तथा कृषि उपज में वृद्धि भी सम्भव हो सकी। इन्होंने इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून भी पारित कराया। इस योजना का लक्ष्य मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप खादों का प्रयोग कर कृषि उपज में वृद्धि करना था। गरीब किसानों के हित में चौधरी चरण सिंह ने कृषि आपूर्ति संस्थानों की योजना चलाई। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को सस्ती खाद-बीज आदि की सुविधा प्राप्त हुई।

कृषि मण्डियों में किसानों के शोषण को रोकने के लिए आजादी के बाद 1949 में जो मण्डी समिति कानून अस्तित्व में आया, वह भी चौधरी चरण सिंह के विचारों पर आधारित था।

मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह -

1967 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और 3 अप्रैल को विरोधी दलों की संयुक्त सरकार बनने पर ये पहली बार मुख्यमंत्री चुने गये। 1970 में ये दोबारा फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए।

1977 में आपात काल के बाद आम चुनाव हुये। चुनाव में जनता पार्टी केन्द्रीय सत्ता में आई। चौधरी साहब पहली बार लोक सभा के सदस्य बने। जनता पार्टी सरकार में वे पहले गृहमंत्री, बाद में 1979 में उप प्रधानमन्त्री तथा वित्त मंत्री बने।

15 जुलाई 1979 को माननीय मोरारजी देसाई के त्याग पत्र के बाद 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री का पद सँभालने के बाद, चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्र के नाम एक संदेश में कहा-

'हमें गरीबी मिटाना है और प्रत्येक नागरिक के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिये यह सुनिश्चित करने से बेहतर कोई देशभक्तिपूर्ण लक्ष्य नहीं हो सकता कि कोई भी बालक भूखा नहीं सोए, किसी परिवार को अपने अगले दिन के भोजन की चिन्ता नहीं हो, और किसी भी भारतीय का भविष्य और क्षमताएँ कुपोषण के कारण अवरुद्ध न हो पाये'।

उन्होंने भारत के 33वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा 'राष्ट्र तभी सम्पन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो।

जातिवाद के विरोधी -

चौधरी चरण सिंह जातिवाद को भारतीय राष्ट्रीयता के लिये सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उनका स्पष्ट विचार था कि जातिवाद के दुष्परिणाम के कारण हम भारतीयों ने सैकड़ों साल गुलामी का जुआ अपने कंधे पर ढोया।

1967 में मुख्यमन्त्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने एक शासकीय आदेश पारित करवा दिया कि जो संस्थाएं किसी जाति विशेष के नाम से चल रही हैं, उनका शासकीय अनुदान बन्द कर दिया जायेगा। इस आदेश के तुरन्त बाद अग्रवाल कालेज-महाराजा अग्रसेन कालेज में, रस्तोगी कालेज महाराजा हरिश्चन्द्र कालेज में और जाट कालेज- महर्षि दयानन्द और वैदिक कालेज जैसे नामों में बदल गए थे। ऐसे काम चौधरी चरण सिंह जैसे संकल्पशील और निर्भीक व्यक्ति ही कर सकते थे।

जातिवाद के दुष्परिणामों का विस्तृत ब्यौरा उनके लेख में मिलता है जो 'कास्टिज्म' (जातिवाद) उप-शीर्षक से उनकी पुस्तक 'इकानोमिक नाइटमेअर ऑफ इण्डिया इट्स कॉजेज एण्ड क्योर' में लिखा गया है।

ईमानदार नेता के रूप में -

चौधरी चरण सिंह ने जीवन में किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। उनका जीवन एक खुली किताब था, जिस पर कोई दाग नहीं लगा।

जब इन्होंने 1970 में मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की तब वे कानपुर में थे। उन्होंने वहीं से सरकारी गाड़ी लौटा दी और प्राइवेट वाहन द्वारा लखनऊ वापस आ गए।

साहित्यकार तथा लेखक के रूप में चौधरी चरण सिंह-

चौधरी चरण सिंह राजनैतिक नेता के साथ-साथ विचारक, लेखक तथा सुधारक भी थे। उन्हें हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं पर अच्छा अधिकार था। इनकी पुस्तक

‘इकोनॉमिक नाइटमेअर ऑफ इण्डिया इट्स कॉजेज एण्ड क्योर’ (भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान) देश विदेश में चर्चित रही। अपनी पुस्तक ‘लैण्ड रिफार्म्स इन यू0पी0 एण्ड दि कुलक्स’ में इन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन का विशद विवेचन किया है। 1941 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह के आन्दोलन के तहत बरेली सेंट्रल जेल में बंद थे, उस समय उन्होंने अपने बच्चों को पत्र लिखे जिनमें उन्हें शिष्टाचार की शिक्षा दी। इन पत्रों को बाद में ‘शिष्टाचार’ शीर्षक के अन्तर्गत पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।

इसके अतिरिक्त हमारी गरीबी कैसे मिटे, इण्डियाज इकोनामिक पॉलिसी, दि गांधियन ब्ल्यू प्रिंट, राष्ट्र की दशा, आर्थिक विकास के सवाल और बौद्धिक दिवालियापन, आदि लेख एवं पुस्तकें प्रसिद्ध हैं।

चरण सिंह मूलतः ग्रामीण भावना से जुड़े हुए भारत के पिछड़े वर्गों, किसानों के प्रिय और बेझिझक सच बोलने वाले नेता थे। भारत के ये जुझारू नेता 29 मई 1987 को हमेशा के लिए किसान घाट, नई दिल्ली पर चिरनिंद्रा में लीन हो गए। भारत अपने इस महान किसान नेता को सदा याद करता रहेगा।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

(क) चौधरी चरण सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था ?

(ख) चौधरी साहब को किसानों का नेता क्यों कहा जाता है ?

(ग) चौधरी चरण सिंह को प्रथम जेल यात्रा क्यों करनी पड़ी ?

(घ) कृषि और कृषकों के लिए चौधरी चरण सिंह ने क्या कार्य किए ?

(ड.) 15 अगस्त पर चौधरी चरण सिंह ने देशवासियों को क्या संदेश दिया ?

(च) चौधरी चरण सिंह की लिखी पुस्तकों के नाम लिखिए।

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) चौधरी चरण सिंह ने......................कानून पारित कराया।

(ख) चौधरी साहब सन्.........................एवं..........................में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

(ग) ....के त्यागपत्र देने पर चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

(घ) चौधरी चरण सिंह...................................के घोर विरोधी थे।

3. सही मिलान कीजिए-

(क) महात्मा गांधी ने डाँडी मार्च कर क. 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ।

(ख) जमींदारी उन्मूलन विधेयक ख. ‘करो या मरो’ का आह्वान किया।

(ग) चौधरी चरण सिंह ग. नमक कानून तोड़ो आन्दोलन चलाया।

(घ) गांधी जी ने देशवासियों से घ. जातिवाद के घोर विरोधी थे।